हिमाचल प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण

1025. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युतीकरण योजनाओं और प्रणाली सुधार योजना (सिस्टम इम्प्रूवमेंट स्कीम) के अन्तर्गत, चालू वर्ष के दौरान, हिमाचल प्रदेश के किन-किन विकास खण्डों में विद्युतीकरण से छूटे हुए गांवों में विद्युतीकरण करने स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) इस संबंध में विकासखंड-वार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड के लिए मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कुल्लू नगर, आनी और निर्मण्ड विकास खण्डों तथा बंजर विकास खण्ड में भी इस प्रकार की योजनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विकास-खण्ड-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विकास खण्ड को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) हिमाचल प्रदेश में जहां व्यवहार्य था, सभी गांवों में विद्युतीकरण कर दिया गया है। प्रणाली सुधार योजनाओं का जहां तक संबंध है, इस संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान ऐसी किसी योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। चूंकि, इस संबंध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के मानदण्डों के अनुसार संशोधित प्रणाली सुधारात्मक स्कीम को अभी प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अन्तर्गत योजनाओं का रखरखाव

1026. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार देश के पर्वतीय राज्यों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में जो विद्युतीकरण किया गया था उसमें अनेक स्थानों पर लकड़ी के खम्बों के सड़े-गले जाने के कारण उनमें लगी हुई विद्युत-तारें लोगों के घरों और खेत-खलिहानों पर बिल्कुल नीचे तक झुक गई हैं जिसके फलस्वरूप आए दिन दुर्घटनायें हो रही है और ट्रांसमिशन का नुकसान बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी राज्य ने इन योजनाओं के अन्तर्गत रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु प्राक्कलन भेजकर तदनुसार धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सामान्यतः राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जिसमें प्रणाली सुधार कार्य भी शामिल है, के नए और मौजूदा वैद्युत ढांचागत कार्य के संवर्धन और उत्थापन कार्य पर आने वाले पूंजीगत व्यय को पूरा कर सकें। सामान्यतः ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा अनुरक्षण, प्रचालन और क्षतिग्रस्त, नेटवर्कों की मरम्मत के कार्य का वित्त पोषण नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त आर.ई.सी. को इस प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य के वित्त पोषण के लिए लागत अनुमानों समेत किसी प्रकार का औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात और महाराष्ट्र में बिजली की आवश्यकता

1027 **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में बिजली की अनुमानित आवश्यकता जिलावार कितनी है ;

(ख) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, विद्युत का वर्तमान उत्पादन कितना है और इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इन राज्यों में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ङ) आठवीं पचवर्षीय योजनावधि के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैयां नायडू) : (क) अप्रैल, 94 से अक्तूबर, 94 की अवधि के दौरान गुजरात तथा महाराष्ट्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

(आंकड़े म.यू. में)

	गुजरात	महाराष्ट्र
आवश्यकता	17140	27405
उपलब्धता	16558	27152
कमी	582	253
प्रतिशत	3.4	0.9

(ख) अप्रैल 94 से जून, 94 के दौरान गुजरात तथा महाराष्ट्र में ऊर्जा उत्पादन निम्न था :—

(आंकड़े मा.यू. में)

	गुजरात	महाराष्ट्र
ताप विद्युत	7282	9932
न्यूक्लीयर	0	214
जल विद्युत	240	1571
कुल :	7522	11717

(ग) तथा (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात तथा महाराष्ट्र में क्षमता अभिवृद्धि:—

परियोजना का नाम	क्षमता मे मे.वा.	अनुमानत लागत (करोड़ रुपये में)	चालू करन का कार्यक्रम
1	2	3	4
गुजरात			
राज्य क्षेत्र :			
कदाना यूनिट–III 3 एवं 4	120	113.00	12/95
कच्छ लिग्नाईट यूनिट–3	70	300.00	04/97

1	2	3	4
सिक्का यूनिट–2	120	211.62	03/93
उत्तरन गैस आधारित टी.पी.	78	227.04	07/93
केन्द्रीय क्षेत्र :			
कवास सी.सी.जी.टी.	538	1494.51	03/93
काकरापाड़	440	745.00	03/95
गांधार सी.सी.जी.टी.	615	2291.27	09/95
2. महाराष्ट्र :			
राज्य क्षेत्र :			
मानकोड	6	12.10	03/95
उज्जैनी	12	43.76	03/93
वारन	16	28.25	01/96
सूर्या	6	12.78	03/95
भिंडरदारा–II	34	51.35	04/95
दूधगंगा	24	47.53	08/95
डिमे	5	10.98	03/95
मीरा पी.एस.एस.	150	85.95	03/95
कोयना चरण–4	500	1090.00	08/97
चन्द्रापुर यूनिट–7	500	962.97	03/97
उरन डब्यू.एच.सी.	360	350.00	04/97
खापरखेडा एक्स.	420	600.00	04/97
ट्राम्बे	180	510.00	11/94
बी.एस.ई.एम. (दाहनु)	500	1472.00	03/95
संयुक्त क्षेत्र :			
सरदार सरोवर	1450	1950.54	03/97

(ङ) गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में विद्युतीकरण हेतु व्यवहार्य सभी गांवों को मार्च, 1989 के अन्त तक पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है। इसलिये, इन राज्यों में गांवों के विद्युतीकरण हेतु चालू वर्ष में कोई निधियां जुटाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

विद्युत कंपनियों का लाभ

1028. **श्री गोपाल जी० सोलंकी** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत कंपनियों को इक्विटी इश्यूज से प्राप्त हुए लाभांश पर 16 प्रतिशत लाभ देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने क्या-क्या मुद्दे उठाए हैं; और

(ग) सरकार ने इन कंपनियों द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) प्रीमियम जो कि स्वयं इक्विटी का है